

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3-1516/दस-2008-308/97
लखनऊ : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय - झाप

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित / समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की स्वीकृत

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत पेंशनर एवं दिनांक 01-10-2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय - झाप संख्या - सा-3-1508/दस-2008, दिनांक 08-12-2008 एवं कार्यालय - झाप संख्या - सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08-12-2008 निर्गत किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औसत महंगाई मूल्य सूचकांक AICPI536 तक के महंगाई राहत के समायोजन के उपरान्त निम्नलिखित तिथियों में दर्शायी गयी दरों पर महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की है।

Date from which payable	Rate of Dearness Relief per mention
01-01-2006	No Dearness Relief
01-07-2006	2% of Basic Pension / Family Pension
01-01-2007	6% of Basic Pension / Family Pension
01-07-2007	9% of Basic Pension / Family Pension
01-01-2008	12% of Basic Pension / Family Pension
01-07-2008	16% of Basic Pension / Family Pension

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 01-07-2006, 01-01-2007, 01-07-2007, 01-01-2008 तथा दिनांक 01-07-2008 में स्वीकृत महंगाई राहत को तालिका में दर्शायी गयी महंगाई राहत जिसे सरकारी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को भुगतान किया जा चुका है, को इस आदेश से अतिक्रमित करते हुए भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि को इन आदेशों के अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत से समायोजित कर ली जायेगी।

इस आदेश के प्रयोजन हेतु :-

(1) ऐसी पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्मिलित है जिसमें कर्मचारी की

16(E)
S. No. 10 to 106/1109
Lkh. No. 120/1109

-2/-

उत्तर प्रदेश शासन (कार्यालय)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ 2001109

उत्तर प्रदेश शासन (कार्यालय)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ 21/11/09

Ac-VII
21/11/09

(326)

सेवानिवृत्ति की दिनांक 01-01-2006 के पूर्व हैं एवं जिन मामलों में पारिवारिक पेंशन दिनांक 01-01-2006 से पूर्व स्वीकृत की गयी है तथा कार्यालय - ज्ञाप संख्या - सा-3-1515/दस-2008, दिनांक-08-12-2008 के अधीन दिनांक 01-01-2006 से समेकन किया गया है।

(2)- ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त हुयी है एवं जिन प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन प्रथम बार दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त स्वीकृत हुई है जिनका निर्धारण कार्यालय - ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008, दिनांक 08-12-2008 के अनुसार किया गया है, उनमें स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन की मूल पेंशन एवं मूल पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी।

1.2- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपया के गुणांक में आगणित होगी उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जायेगा।

1.3- पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में यथा सेवायोजित / पुर्नयोजित पेंशनर एवं जिन मामलों में एक से अधिक पेंशन अनुमन्य है शेष व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेगी।

2- यह आदेश सभी सरकारी सिविल पेंशन / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होंगे।

2.1

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्मित किया जाना अपेक्षित होगा।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व से निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:सा-3-1508 / दस-2008-308-97
लखनऊ : दिनांक : 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय - झाप

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरो के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिनांक 01-01-2008 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण / समायोजन किया जायेगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरो पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेंनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या - सा-3-969 / दस-933 / 85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अश्वतता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरो पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकरणों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

2-(1) प्रभावी होने की तिथि -

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

2-(2)

जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन

--2/--

HEV

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी (स्वायत्त)
उत्तर प्रदेश

21/1/09

(328)

महाविदेशिक (कार्मिक)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ 120/1/09

के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसे पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3-(1) परिलब्धियों -

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक / डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि मूल नियम - 9 (21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

3-(2)

" वेतन " से आशय उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान में पे बैंड तथा लागू ग्रेड पे से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

3-(3)

सेवानिवृत्ति / डेथ ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महँगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जायेगा।

4-पेंशन

पेंशन की गणना पूर्व की भौति, औसत परिलब्धियों पर दिये जाने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में पुनर्स्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा पे ग्रेड के योग के 50 प्रतिशत के आधार पर भी की जायेगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगा परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनाशि रू० 3500/- प्रतिमाह से कम तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन (दिनांक 01-01-2006) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तदनुसार राज्य सरकार की पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

4-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद - 474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

4-(2)

वर्तमान में राज्य सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है परन्तु तत्काल प्रभाव से उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी, सेवा करना अनिवार्य है। जो सरकारी

सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के आधार पर, जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी।

4-(3)

ऐसे सरकारी सेवक जो दस वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होते हैं तथा पेंशन पाने के पात्र हैं, उन्हें भी उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

4-(4)

उपरोक्त प्रस्तर -4(2) एवं 4(3) की व्यवस्था इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा उन सरकारी कार्मिकों पर लागू होंगे जो उक्त दिनोंक को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे। जो सरकारी सेवक दिनोंक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु इस कार्यालय - झाप के जारी होने के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं उन पर पेंशन संबंधी वही नियम लागू होंगे जो इस कार्यालय - झाप के जारी होने की तिथि के पूर्व लागू थे।

4-(5)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा रू0 3500/- प्रतिमाह तथा अधिकतम सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम वेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। (राज्य सरकार में दिनोंक 01-01-2006 से अधिकतम वेतन की धनराशि रूपया 80,000/- है)

4-(6)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स की संबंधित व्यवस्थाएँ उपरोक्त प्रस्तर - 1 से 5 में पुनरीक्षित व्यवस्था के अनुसार संशोधित समझी जाएगी। शेष व्यवस्थाएँ यथावत् लागू रहेंगी।

4-(7)

वरिष्ठ पेंशनरों को सामान्य अनुमन्य पेंशन की धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित अतिरिक्त पेंशन भी अनुमन्य की जाएगी :-

पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष की आयु से कम	मूल पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु अथवा अधिक	मूल पेंशन का 100% प्रतिमाह

-4/-

(330)

पेंशन स्वीकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार - पत्र में पेंशनर की जन्मतिथि एवं आयु का स्पष्ट उल्लेख करें जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पी०पी०ओ० में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जाएगी उदाहरणतया यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष है और उसकी पेंशन की धनराशि रूपया 10,000.00 प्रतिमाह है तो उसमें मूल पेंशन रूपया 10,000/- तथा (ख) अतिरिक्त पेंशन रूपया 2,000 होगी। इसी प्रकार से 85 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन (क) रूपया 10,000.00 (ख) अतिरिक्त पेंशन रूपया 3,000 प्रतिमाह होगी।

5- ग्रेच्युटी

5-(1)

सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपया 10 लाख होगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स 1961 को संबंधित नियम को दिनांक 01-01-2006 से संशोधित समझा जाएगा तथा नियम के अधीन सेवानिवृत्तिक / मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू० 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

6-अर्हकारी से अतिरिक्त सेवा की गणना

उपरोक्त प्रस्तरो 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित नियम तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

7- नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965

पारिवारिक पेंशन की धनराशि सभी प्रकरणों में सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय आहरित मूल वेतन के 30 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम 24,000/- होगी।

7-(1)

वर्तमान में राज्य सरकार में सरकारी सेवक / पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 07 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा सामान्य पेंशन से दुगुनी दर अथवा सामान्य दशा में अनुमन्य पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 01-01-2006 से तथा उसके उपरान्त के प्रकरणों में 07 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि में कोई संशोधन नहीं होगा। पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

7-(2)

वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि में निम्न प्रकार से अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशनर की आयु	पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 20% प्रतिमाह
85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 30% प्रतिमाह
90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 40% प्रतिमाह
95 वर्ष परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह

उपरोक्त अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के लिए शेष सभी कार्यवाही उपरोक्त प्रस्तर-4(7) के अनुसार की जाएगी।

7-(3)

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा :-

वर्ग - I

- (क) विधवा / विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,
 (ख) पुत्र / पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग - (II)

- (ग)- अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग- I से आच्छादित नहीं है, को विवाह / पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

- (घ)- ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा / विधुर अथवा बच्चे नहीं होती है।

आश्रित माता - पिता अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग - II से आच्छादित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता / पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसी ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की पात्रता स्थापित होगी।

7-(4)

उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महंगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7-(5)

सतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सगी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाएगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जाएगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाण - पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

8-पेंशन के एक भाग का राशिकरण

8-(1)

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी का राशिकरण करा लें।

9-(2)

पेंशन सराशिकरण की तालिका सम्बद्ध है तथा इस हेतु 30प्र0 कम्प्यूटेशन आफ पेंशन रूल्स को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

8-(3)

पेंशन राशिकरण से संबंधित पुनरीक्षित तालिका उन सभी प्रकरणों में प्रभावी होगी जिनमें इस कार्यालय - ज्ञाप के निर्गत होने के उपरान्त राशिकरण कराया गया है जिन प्रकरणों में पेंशन राशिकरण की कार्यवाही इस कार्यालय - ज्ञाप के निर्गत होने से पूर्व सम्पन्न की जा चुकी है, उनमें राशिकरण की पूर्ण तालिका में दर्शायी गयी दरों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों को यह विकल्प भी होगा कि दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित अतिरिक्त पेंशन के एक भाग (अधिकतम सीमा तक) का राशिकरण करा लें। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का राशिकरण का भुगतान पेंशन राशिकरण की नई तालिका में निर्धारित की गयी दरों के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यालय - ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त राशिकरण के प्रकरणों में नई तालिका के अनुसार धनराशि आगणित की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्प्यूटेशन) रूल्स उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

(333)

- 1 / -

9- एवस-ग्रेसिया एक मुश्त कम्पेन्सेशन

वर्तमान व्यवस्था के अधीन जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु सरकारी कार्य के दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एवस-ग्रेसिया की धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। इस कार्यालय - ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से पूर्व निर्धारित दरों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

रूपया

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10,00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं / अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुलम पहाड़ी ऊर्चाइयों / दुलम सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15,00 लाख

संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

10-

ऐसे सरकारी कार्मिकों जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 से लागू नये वेतनमान को वर्णन करने का विकल्प दिया है, विकल्प देने की तिथि से 10 माह की अवधि के अन्दर प्रवानिवृत्त हो जातें है, उनकी पेंशन की गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी :-

- (क)- पुनरीक्षित वेतनमान / निर्धारित पे बैंड तथा ग्रेड पे में आगणित धनराशि।
- (ख)- शेष अवधि के लिए दिनांक 01-01-2006 से पूर्व में अवधि में आहरित मूल वेतन / महँगाई वेतन तथा वास्तविक महँगाई भत्ता, जो कि दिनांक 01-01-2006 को प्रभावी थे तथा संगत अवधि में आहरित किया गया है।

(334)

सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 के पूर्व में प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है, के संबंध में विशेष व्यवस्था :-

12- ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने दिनांक 01-01-2006 के पूर्व प्रभावी वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प दिया है और अब दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन / मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा :-

- (1)- " परिलब्धियों " शब्द से तात्पर्य उस वेतन से हागा जो मूल नियम 9(21)(ए)(1) तथा उस पर महँगाई वेतन तथा औसत AICPI-536 तक अनुमन्य महँगाई राहत (वर्ष 1982 = 100 के आधार पर) पर आगणित होगी।
- (2)- पेंशन की गणना परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर अथवा औसत परिलब्धियों, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पर की जाएगी।
- (3)- मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी की गणना हेतु उपरोक्त 12(1) में परिभाषित परिलब्धि तथा उस पर इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व अनुमन्य महँगाई भत्ता सम्मिलित होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि की अधिकतम सीमा रूपया 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।
- (4)- पेंशन राशिकरण की दरें वही होगी जैसा कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थे।
- (5)- पारिवारिक पेंशन की गणना / स्वीकृति उसी प्रकार होती रहेगी जैसी कि इन आदेशों के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी थी एवं उसी गणना दिनांक 01-01-2006 से पूर्व लागू वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त गणना हेतु AICPI-536 (वर्ष 1982-100 के आधार पर) निर्धारित महँगाई राहत, जैसी कि शासनादेश संख्या-सा-3-1746/दस-308/05, दिनांक 02-12-2005 में बताई गयी है को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार आगणित पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर AICPI-536 औसत के उपरान्त ही महँगाई राहत की गणना की जाएगी।
- (6)- उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन / उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 / उ0प्र0 लिबरलइज पेंशन रूल्स 1961 / उ0प्र0 असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन स्कीम के आधीन यथाआवश्यक नियम / व्यवस्थाएँ संशोधित समझे जाएँगे तथा शेष नियम / व्यवस्थाएँ पूर्ववत् रहेगी।

(7)- इस कार्यालय- झाप के आधार पर आगणित / अनुमन्य पेशन / पारिवारिक पेशन पर AICPI-536 के औसत के उपरान्त अनुमन्य कराये जाने वाला महँगाई राहत अनुमन्य होगा।

(8)-अवशेष भुगतान की प्रकिया

दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 30-11-2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जाए। पेशनरों / पारिवारिक पेशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेशनरों / पारिवारिक पेशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए। पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेशनर / पारिवारिक पेशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेशनर / पारिवारिक पेशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेशनर / पारिवारिक पेशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

(संज्ञा १०००)

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1)-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
- (2)-समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०,
- (3)-समस्त जिला अधिकारी, उ०प्र०

स्थानीय पेशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालयसूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

संख्या - सा-3-1508(1)/दस-2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ
- प्रत्येक को पाँच

प्रत्येक को एक प्रति
-5 प्रतियाँ-

- 3- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ -5 प्रतियों
- 4- निदेशक, पेशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ -5 प्रतियों
- 6- सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को प्रचारार्थ। -5 प्रतियों
- 7- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद -5 प्रतियों
- 8- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। -5 प्रतियों
- 9- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर। -5 प्रतियों
- 10- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ। -5 प्रतियों
- 11- इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। -5 प्रतियों
- 12- मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। -5 प्रतियों

नागरिक उद्ययन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ०प्र० लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियों, उ०प्र०, महानिरीक्षक, होमगार्ड्स, उ०प्र० प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र० लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झॉंसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

आज्ञा से,

(337)

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

ANNEXURE

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Rs. 1
PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.190	61	8.194		

20/1

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या:सा-3-1515 / दस-2008-308-97

लखनऊ दिनांक : 8 दिसम्बर, 2008

कार्यालय - ज्ञाप

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2008 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 01-01-2008 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत सभी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों के अभिनवीकरण / पुनरीक्षण के संबंध में निम्न आदेश प्रदान किए हैं।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश लिब्लराइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या - सा-3-969/दस-933/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे। किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकरणों आदि व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

3-इन आदेशों के अन्तर्गत

(क)- "वर्तमान पेंशनर " अथवा " पारिवारिक पेंशनर " का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-2005 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन / पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन / पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)- "वर्तमान पेंशन " का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31-12-2005 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर -2 में किया गया है।

(ग)- "वर्तमान पारिवारिक पेंशन " का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो

16(E)

01.11.09 to 20.11.09
for necessary action.

-2/-

Huv

Huv

पुलिस महानिदेशक (कार्य)

उत्तर प्रदेश

21.11.09

Huv

उत्तर पुलिस महानिदेशक (कार्य)

20/11/09

(339)

02/11/09

19-1-09

नयी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या - सा-3-657/दस-900/78, दिनोंक 10-05-1978 अथवा शासनादेश संख्या - सा-3-1563/दस-921/81, दिनोंक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनोंक 31-12-95 को अथवा शासनादेश संख्या - सा-3-969/दस-923/85, दिनोंक 08-08-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनोंक 31-12-05 को अनुमन्य थी।

4-(1)

ऐसे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो दिनोंक 01-10-2006 के पूर्व से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का समेकन दिनोंक 01-01-2006 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करके किया जायेगा :-

- (I)- वर्तमान पेंशन / पारिवारिक पेंशन,
- (II)-महेंगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य हो,
- (III)- वर्तमान महेंगाई राहत जैसा कि औसत AICPI536 (वर्ष 1982-100 के आधार पर) मूल पेंशन / मूल पारिवारिक पेंशन तथा महेंगाई पेंशन के 24 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य है शासनादेश संख्या -सा-3-1746/दस-2005-308/2004, दिनोंक 02 दिसम्बर, 2005 के अनुसार महेंगाई राहत के 50 प्रतिशत के बराबर धनराशि को महेंगाई पेंशन में परिवर्तित करते हुए,
- (IV)-पेंशन / पारिवारिक पेंशन के 40 प्रतिशत के फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि भी सम्मिलित होगी।

जिन प्रकरणों में वर्तमान पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महेंगाई राहत की धनराशि सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेन्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महेंगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जाएगी।

इस प्रकार आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन को दिनोंक 01-01-2006 से मूल पेंशन माना जाएगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे ब्रेण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि अनुपातिक रूप में कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनोंक 01-01-2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे ब्रेण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 30 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

4-(2)

क्योंकि उपरोक्त प्रकार आगणित पेंशन की धनराशि में पेंशन के राशिकरण का अंश भी सम्मिलित है, इसलिए मासिक भुगतान में उक्त अंश को घटा दिया जाएगा।

(340)

और

पेंशन / पारिवारिक पेंशन की दिनांक 01-01-2006 के पूर्व न्यूनतम / अधिकतम सीमा कमशः रूपया 1275 एवं रू0 13000 थी, दिनांक 01-01-2006 से रूपया 3500 तथा 40,000 हो जाएगी।

4-(4)

वृद्ध पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशनरों की धनराशि में निम्न प्रकार वृद्धि की जाएगी :-

पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20%
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक का 30 प्रतिशत
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक की धनराशि का 40 प्रतिशत
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 50% प्रतिमाह .
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 100% प्रतिमाह

पेंशन भुगतानादेश में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से दर्शायी जाएगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- है, उस दशा में उसके सम्मुख रू0 2000/- प्रतिमाह अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी पेंशन एवं अतिरिक्त पेंशन दर्शायी जाएगी। उपरोक्त प्रकरणों में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि अवश्य अंकित की जाएगी। जिससे कि भुगतान में कठिनाई न हो।

4-(5)

वर्तमान में ऐसे पेंशनर जो दिनांक 31-03-1985 तथा 31-12-1985 के मध्य सेवानिवृत्त हुए और जिन्हें "व्यैक्तिक पेंशन" पेंशन मिल रही है, वे उसे पूर्व की भाँति प्राप्त करते रहेंगे तथा उसे पेंशन समेकन में शामिल नहीं किया जायेगा।

4-(6)

उपरोक्त प्रकार से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की धनराशि में औसत सूचकांक 536(1982=100 बेस वर्ष) के अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत सम्मिलित

है, इस कारण अब उक्त सूचकांक के ऊपर बढ़ी हुयी महँगाई राहत का भुगतान अनुमन्य होगा। महँगाई राहत के भुगतान के संदर्भ में आदेश अलग से निर्गत किए जा रहे हैं।

5- यदि समेकित पेंशन / पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500 /- प्रतिमाह से कम आती है तो उसे रू0 3500 /- प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा इसे दिनांक 01-01-2006 से मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन माना जायेगा। जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त है, उनकी दोनों पेंशनें अधिकतम सीमा रू0 3500 प्रतिमाह होगी।

5-(1)

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को यदि सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अधीन भी पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उन प्रकरणों में भी दोनों पेंशनों का योग रू0 3500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। यदि केवल अशक्तता पेंशन स्वीकृत की गयी है तो उसकी न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 से कम नहीं होगी। जहाँ केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है। उक्त धनराशि केवल उन प्रकरणों में भुगतान की जाएगी जिनमें 100 प्रतिशत अशक्तता प्रमाणित है तथा यदि अशक्तता की श्रेणी कम है तो उन प्रकरणों में उसी अनुपात में पेंशन घटा दी जाएगी।

6 - सेवायोजित / पुनर्योजित पेंशनर

सेवायोजित / पुनर्योजित पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों पर वर्तमान में महँगाई राहत अनुमन्य नहीं है। उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु प्रकल्पित महँगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायेगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती। यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित / पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उनकी पेंशन का समेकन किया जायेगा। दिनांक 01-01-2006 से उनका वेतन उपरोक्तानुसार आगणित / समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से संबंधित महँगाई राहत उन्हें सेवायोजन / पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी।

7- सरकारी सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन पर पेंशन की व्यवस्था।

(क) - पेंशन :-

ऐसे सरकारी सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को भी इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु उन प्रकरणों में पुनरीक्षित नहीं

किया जायेगा जिनमें आमेलित कार्मिक को उसकी 100 प्रतिशत पेंशन की एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-12-1975 के अधीन राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन किया जा चुका है।

(ख)-पारिवारिक पेंशन:-

ऐसे प्रकरणों में जिनमें सरकारी उपक्रम / स्वायत्तशासी संस्थाओं में आमेलन के उपरान्त कार्मिक की मृत्यु के फलस्वरूप पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है, उन पारिवारिक पेंशनों का भी पुनरीक्षण किया जायेगा।

उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अधीन पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की गणना करते हुए एक तालिका बनायी गयी है जो इस आदेश के साथ संलग्न है। समस्त कोषागार इस तालिका के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में अलग से प्राधिकार - पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग)-भुगतान की प्रक्रिया:-

दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 30-11-2008 तक के देय अवशेष का 20 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत भाग वित्तीय वर्ष 2009-10 में तथा शेष 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया जायेगा। पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को विभिन्न वित्तीय वर्षों में देय अवशेष का भुगतान नकद किया जाए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए।

किसी पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किए जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों के देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान कर दिया जाए।

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1)-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
- (2)-समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०,
- (3)-समस्त जिला अधिकारी, उ०प्र०

स्थानीय पेशनरों को रांघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालयसूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

संख्या - सा-3-15(1)/दस-2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 1- | सचिवालय के समस्त अनुभाग। | प्रत्येक को एक प्रति |
| 2- | सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ। | -5 प्रतियाँ- |
| 3- | निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ | -5 प्रतियाँ- |
| 4- | निदेशक, पेशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ | -5 प्रतियाँ- |
| 6- | सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को प्रचारार्थ। | -5 प्रतियाँ- |
| 7- | मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद | -5 प्रतियाँ- |
| 8- | मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। | -5 प्रतियाँ- |
| 9- | वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर। | -5 प्रतियाँ- |
| 10- | उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ। | -5 प्रतियाँ- |
| 11- | इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। | -5 प्रतियाँ- |
| 12- | मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ। | -5 प्रतियाँ- |

नागरिक उद्यन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ०प्र० लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, महानिरीक्षक, होमगार्ड्स, उ०प्र० प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल,

आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक
सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र०
लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, परिवार
कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, शिक्षा विभाग,
प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल
कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल
कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झॉंसी, मेडिकल कालेज,
गोरखपुर।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश
विशेष सचिव